वाह री फरीदाबाद पुलिस : छुटभैयों पर कार्रवाई, मंत्री के खास को सलामी

-विकास तीर्थ यात्रा में हाइवे पर मंत्री कृष्णपाल गूजर के साथ स्टंट करते लोग पुलिस को नहीं आए नजर
-भाजयुमो के महासंपर्क अभियान में एक छुटभैये नेता का चालान काट पीठ थपथपा रही पुलिस

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा के मातहत कानून की नजर में सबको बराबर नहीं समझते। सत्ता में जिसकी जितनी ज्यादा पैठ उस पर उतनी ही मेहरबानी, आम नागरिक है तो उसे कोई छूट नहीं है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर आम आदमी का चालान काटने वाली पुलिस सत्ता के छुटभैये नेताओं पर हल्की फुल्की कार्रवाई करती है या खानापूर्ति के लिए चालान थमाया जाता है। अगर मामला सांसद-विधायक, मंत्री या उसके खास का हो तो चालान काटना दूर पुलिस तो आगे-आगे चलकर इन स्टंट करने वालों का रास्ता साफ कराती है।

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गूजर ने छह जून को दिल्ली-मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेस पर विकास तीर्थ यात्रा निकाली थी। यात्रा में शामिल कारों के काफिले में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता खतरनाक ढंग से बाहर लटक कर स्टंट करते नजर आए। यहां तक कि कृष्णपाल गूजर की कार पर भी चार-चार लोग पांवदान पर लटक कर नारेबाजी करते हुए देखे गए। क्योंकि काफिला केंद्रीय मंत्री का था इसलिए यातायात पुलिस उसमें शामिल वाहनों के चालकों को स्टंट नहीं करने और सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की नसीहत नहीं दे सकी, बल्कि उनके लिए रास्ता साफ करते हुए आगे चलती दिखी। अखबारों में मंत्री और उनके समर्थकों द्वारा ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने की खबर भी छपीं लेकिन सत्ता के आगे नतमस्तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

इधर, मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने की खुशी में भाजयुमो नेता पंकज सिंगला ने भी 10 और 11 जून को तिगांव विधानसभा क्षेत्र में महासंपर्क अभियान रैली निकाली। रैली में करीब पचास बाइकों पर बिना हेलमेट पहने भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य सड़क पर खूब स्टंट दिखाए। मज़दूर मोर्चा ने गतांक में 'इनके सिर पर है सत्ता का हेलमेट, इसलिए पुलिस नहीं करती कार्रवाई' शीर्षक से खबर छापी तो पुलिस को कुछ शर्म महसूस हुई।

मामला सत्ता के छुटभैये नेता का था इसलिए पुलिस ने सिर्फ एक बाइक का चालान काट कर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। पुलिस ने यात्रा में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले अन्य करीब आधा सैकड़ा दोपहिया वाहनों का चालान करना तो दूर उनके मालिकों की पहचान कर नोटिस भेजने तक की जहमत नहीं उठाई। जबकि पंकज सिंगला से लेकर गोल्डी अरोड़ा, योगेश तेवतिया, कार्तिक वशिष्ठ, गौतम भड़ाना सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने महासंपर्क रैली की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया से शेयर की थीं। आम बाइक या कार चालक की एक-एक गलती बारीकी से तलाशने वाली पुलिस का सत्ताधारियों पर कार्रवाई न करना समझा जा सकता है कि उस पर सत्ता का खौफ किस हद तक है।

मॉडल संस्कृति स्कूल : ढोल के अंदर पोल ही पोल

'बैग फ्री' शिक्षा का ढिंढोरा पीटा गया लेकिन विद्यार्थियों के लिए सुविधाएं शून्य

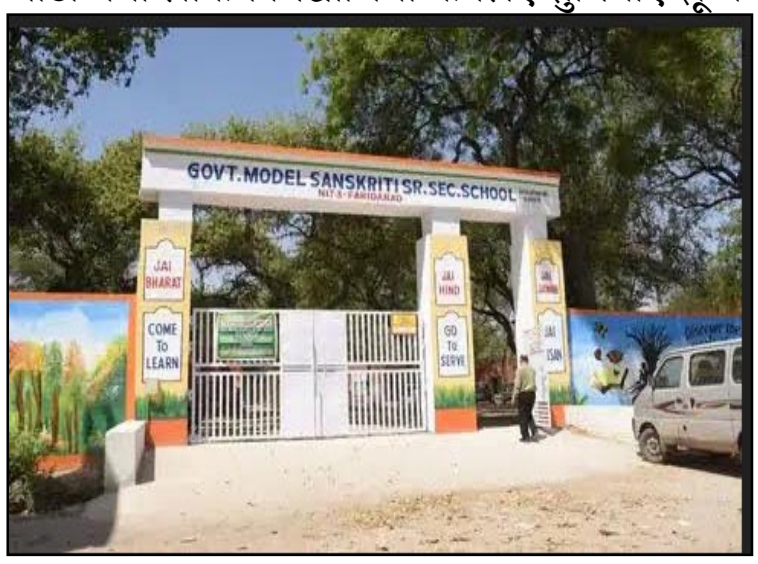

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जब घोषणावीर खट्टर सरकार हो और मुनेश चौधरी जैसी जिला शिक्षा अधिकरी तो जिले में शिक्षा का भट्ठा बैठना तय ही है। खट्टर ने सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसी आधुनिक शिक्षा और 'बैग फ्री' एजुकेशन के देने के लिए अगस्त 2020 में मॉडल संस्कृति स्कूल संचालित करने की घोषणा की थी। घोषणा तो कर दी लेकिन स्कूलों को आधुनिक शिक्षण संसाधन उपलब्ध ही नहीं कराए गए, रही सही कसर काम से दूर भागने वाली डीईओ मुनेश चौधरी ने पूरी कर दी, उन्होंने भी इन स्कूलों के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आधुनिक शिक्षा के नाम पर प्रति माह फीस के रूप में अच्छी खासी रकम वसूलने वाले जिले के ये मॉडल संस्कृति स्कूल भी साधारण स्कूलों की तरह ही चल रहे हैं।

मॉडल संस्कृति स्कूलों के लिए खट्टर सरकार ने बड़े मानक तय किए थे। इसके तहत इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब, करिकुलर (पाठ्यक्रम) एक्टिविटी रूम, डिजिटल रूम, लाइब्रेरी की व्यवस्था की जानी थी। डिजिटल शिक्षा के लिए इंटरनेट वाईफाई सुविधा, अबाध बिजली आपूर्ति के लिए सोलर पैनल की व्यवस्था होनी थी। विद्यार्थियों की अटेंडेंस भी बायोमीट्रिक सिस्टम से लगनी थी। विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए आधुनिक स्पोर्ट्स नर्सरी और हॉस्टल सुविधा की व्यवस्था की जानी थी। स्कूलों की आग से सुरक्षा के लिए फायर फायटिंग सिस्टम, हर कमरे में स्मोक डिटेक्टर, अलार्म, सीसीटीवी लगाए जाने थे।

क्योंकि सरकार के पास नए स्कूल खोलने के इंतजाम नहीं थे इसलिए पुराने चल रहे स्कूलों में ही मॉडल संस्कृति स्कूल चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत फरीदाबाद में 66 प्राइमरी और चार सीनियर सेकेंडरी तथा बल्लभगढ़ में एक सीनियर सेकेंडरी और 55 प्राइमरी मॉडल संस्कृति स्कूल चुने गए। इन स्कूलों के लिए शिक्षक भी अलग से नियुक्त होने थे, जो सरकार के पास आज तक भी नहीं हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एजुकेशन वालंटियर भी तैनात किए जाने थे। शिक्षक भर्ती करने के बजाय संघ के सेवक घुसेड़ने की योजना बनाई गई थी।

आरटीआई एक्टिविस्ट रवींद्र चावला ने इस संबंध में जानकारी मांगी तो स्कीम की हकीकत सामने आई। उसके अनुसार किसी भी स्कूल में फायर फायटिंग सिस्टम, सीसीटीवी, स्मोक डिटेक्टर, अलार्म आदि नहीं लगे थे।

सोलर पावर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई। किसी भी स्कूल में न तो वाइफाई था न स्मार्ट क्लासरूम, स्पोर्ट्स नर्सरी और हॉस्टल सुविधा तो दूर की बात। किसी भी स्कूल में एक भी एजुकेशन वालंटियर तैनात नहीं किया गया, शायद कोई भी संघी सेवक इस तरह की सेवा करने को तैयार नहीं मिला। यानी मॉडल स्कूल की खट्टर की यह घोषणा भी जुमला ही साबित हुई।

25 हजार जुर्माना लगने के बाद भी नहीं सुधरी मुनेश चौधरी

आला अफसरों के आदेश को हवा में उड़ाने वाली फरीदाबाद की डीईओ मुनेश चौधरी आरटीआई कानून के तहत जवाब देने में भी विश्वास नहीं रखतीं। उनकी जवाब न देने की हठधर्मी पर राज्य सूचना आयोग ने नाराजगी जताते हुए उनके लिए एडवायजरी जारी की है कि वह ठीक से काम करें और प्रथम अपीलीय अधिकारी होने के नाते शिकायतों की गंभीरता से सुनवाई कर जवाब दिलाया करें। राज्य सूचना आयोग की यह नाराजगी पहली बार नहीं है, हाल ही में आयोग ने उन पर सूचना नहीं देने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। आरटीआई कार्यकर्ता अजय बहल ने स्कूलों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस लगाए जाने के संबंध में 2019 में जानकारी मांगी थी जो आज तक नहीं दी गई जिस पर आयोग ने मुनेश चौधरी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। दरअसल इसमें मुनेश चौधरी का कुसूर नहीं है, वह तो अपनी छुट्टी की दरख्वास्त तक नहीं लिख सकती, फाइलों पर नोटिंग करना तो दूर की बात है। सारा काम बाबू चला रहे हैं, यही वजह है कि वह न तो बैठकों में जाती है और न ही राज्य सूचना आयोग के बुलावे पर हाजिर होती हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता रवींद्र चावला ने मॉडल संस्कृति स्कूलों की व्यवस्था जानने के लिए जुलाई 2022 में आरटीआई डाली थी। जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी के मातहत सूचना अधिकारी बीईओ मनोज मित्तल ने जवाब ही नहीं दिया। इस पर उन्होंने प्रथम अपीलीय अधिकारी डीईओ मुनेश चौधरी के कार्यालय में 20 सितंबर 2022 को अपील की। मुनेश चौधरी ने न जवाब ही दिलाया और न ही रवींद्र चावला को बुलवा कर मामले की सुनवाई की। इस पर उन्होंने 14 नवंबर 2022 को राज्य सूचना आयोग में अपील की। वहां भी मनोज मित्तल कभी आधी अधूरी जानकारी लेकर पहुंचे तो कुछ और। अंत में राज्य सूचना आयोग ने बीईईओ मनोज मित्तल को कारण बताओ नोटिस जारी कर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने की कड़ी चेतावनी दी तब उन्होंने 20 जून 2023 को रवींद चावला को इसका जवाब भेजा। आयोग ने प्रथम अपीलीय अधिकारी डीईओ मुनेश चौधरी की कार्यशैली पर भी आक्रोश जताया। मुनेश चौधरी बीते दो महीने से घर बैठी है और अगले तीन महीने तक घर बैठी रहेगी, महत्वपूर्ण पोस्ट खाली हैं लेकिन ये पोस्ट जानबूझ कर खाली रखी जा रही हैं ताकि मुनेश घर बैठकर बाबुओं के जरिए काम करवाती रहे। अगर कोई ढंग का बीईओ आ गया तो मुनेश चौधरी के सारे काले कारनामों की पोल खुल जाएगी।

रिवाज़पुर में किस मुंह से निकालोगे गौरवशाली भारत यात्रा

डंपिंग यार्ड नहीं हटाए जाने से नाराज 16 गांव वालों ने यात्रा का विरोध करने का निर्णय लिया

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) जनता की जायज मांगों को कुचलने के हथकंडे अपनाने वाली नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री कृष्णपाल गूजर भी रिवाज़पुर के लोगों के विरोध के बावजूद डंपिंग यार्ड वहीं बनाने के लिए अड़े हुए हैं। मंत्री की जिद के आगे नतमस्तक प्रशासन ने ऐसा दबाव बनाया कि एक किशोर की जान तक चली गई और दो माह में भी हल नहीं निकल सका है। इन गांव वालों के पास अब राजनीतिक रूप से विरोध करने का ही रास्ता बचा है। इसीलिए भाजपा की गौरवशाली भारत यात्रा का विरोध करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

रिवाज़पुर गांव में डंपिंग यार्ड बनाए जाने के विरोध में बीते दो महीनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। विरोध की अगुवाई कर रहे पारस भारद्वाज ने इस संबंध में अरावली गोल्फ क्लब में प्रेसवार्ता कर बताया कि वह लोग केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गूजर, तिगांव विधायक राजेश नागर से लेकर कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी तक सबसे मिल चुके हैं। आज तक कहीं से उचित जवाब नहीं मिला। 25 जून को भाजपा की गौरवशाली भारत यात्रा निकाली जानी है। इसमें जनसमर्थन जुटाने के लिए अब सभी नेता लालायित हैं, इसलिए प्रशासन की ओर से समस्या का समाधान करने के लिए चार से छह दिन का समय मांगने के नाम पर झांस दिया जा रहा है।

दरअसल, कृष्णपाल गूजर कह चुके हैं कि चाहे 65 गांव विरोध करें या 144 गांव इकट्ठा हो जाएं डंपिंग यार्ड तो रिवाज़पुर में ही बनेगा, लेकिन वह यात्रा के दौरान इन गांवों का समर्थन भी चाहते हैं। पारस भारद्वाज ने ऐलान किया कि गौरवशाली भारत यात्रा में 16 गांवों के लोग शामिल नहीं होंगे और आसपास के गांव वालों से भी इस यात्रा में नहीं शामिल होने की अपील की जाएगी। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जो गांव गांव जनसंपर्क करेगी। जिस जनता के वोट से कृष्णपाल गूजर सांसद और मंत्री बने उसके खिलाफ तुगलकी फरमान सुना दिया, उन्होंने न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह की न एनजीटी के आदेश और न ही म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की सिफारिशों की परवाह की। इसके तहत डंपिंग यार्ड उन जगहों पर नहीं बनाया जा सकता जहां आसपास शैक्षिणक संस्थान हों, कोई बड़ी नदी गुजरती हो। रिवाज़पुर गांव में जहां डंपिंग यार्ड बनाया जाना तय हुआ है उसमें तालाब की जमीन आती है, गांव के करीब ही कई विद्यालय और स्वास्थ्य व चिकित्सा संस्थाएं हैं। यमुना नदी भी करीब डेढ़ किलोमीटर दूर से गुजर रही है। इसके अलावा डंपिंग यार्ड बनाए जाने से पहले इलाके का भौगोलिक सर्वे, भूजल स्तर की माप कराई जानी चाहिए। डंपिंग यार्ड उपजाऊ और कृषि योग्य भूमि के करीब नहीं होना चाहिए। डंपिंग यार्ड और आबादी के बीच एक बफर जोन होना चाहिए ताकि कचरे और मानव के बीच सीधा संबंध न रहे। पारस भारद्वाज के मुताबिक इनमें से कोई भी मानक शासन प्रशासन ने पूरे नहीं किए हैं। यदि सरकार नहीं मानी तो संविधान द्वारा दिए गए जीवन का अधिकार हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।